







# प्लास्टिक की बोतलों का मिलेगा पेमेंट

## सीएम ने किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं प्लास्टिक की बोतल को बार कोड से स्कैन कर डिजिटल पेमेंट प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक की खपत को कम करने एवं अधिक से अधिक प्लास्टिक को रिसाइकल कर उसे इस्तेमाल में लाने के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को धरातल में उतारने के लिए समन्वय से कार्य किए जाएं। यह पहल चार धाम यात्रा एवं पर्यटन स्थलों में भी कूड़े की खपत को कम करते हुए स्वच्छता का वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक की समस्या संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती



प्लास्टिक पैकेजिंग में भंडारित पदार्थों का प्रयोग करने के पश्चात प्लास्टिक अपशिष्ट को नजदीकी डी.डी.आर.एस सेंटर को वापस किया जाएगा। बार कोड स्कैन करने के पश्चात उपभोक्ता को प्रत्येक प्लास्टिक अपशिष्ट पर एक निश्चित धनराशि वापस की जाएगी। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के लागू होने से प्लास्टिक कचरे को सर्कुलर इकोनॉमी में वापस लाया जा सकेगा। जिससे संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण समिति श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, विशेष सचिव/मैबर सिक्रेटरी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉ. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव श्री युगल किशोर पंत, श्री आलोक कुमार पाण्डेय एवं वचुंअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।

बन गई है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों में प्लास्टिक की बड़ी समस्या के तौर पर सामने आती है। इसके समाधान हेतु राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। राज्य में स्वच्छता का वातावरण बनाते हुए क्लीन उत्तराखण्ड, ग्रीन उत्तराखण्ड पर सरकार विशेष फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम को 2 साल

पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखण्ड में लाया गया था। जिसके सफल संचालन के लिए उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग जिले को डिजिटल इंडिया अवॉर्ड-2022 से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि नदियां, जंगल, पहाड़ राज्य की धरोहर और पहचान है। प्लास्टिक हमारी इन धरोहरों को खतरे में डाल रही है। जिसके

निस्तारण के लिए राज्य सरकार विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक के प्रयोग से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। जिससे भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में नई क्रांति का संचार हुआ था। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की स्वच्छता के लिए अनेक कार्य हो रहे हैं। इस

अवसर पर जानकारी दी गई कि डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण सरल हो जाएगा। डी.डी.आर.एस के तहत प्लास्टिक बोतल/प्लास्टिक पदार्थों का उत्पादन करने वाली इकाइयों द्वारा 'क्यूआर कोड सिस्टम' जनित किया जाएगा। जिससे उपभोक्ताओं द्वारा

## स्वामी हरि चैतन्य पुरी ने इंटर कालेज में किया टीन शेड का शिलान्यास

गढ़ीनेगी (उद संवाददाता)। क्षेत्र के ग्राम करनपुर में स्थित ए.एन.झा. इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विशाल टीनशेड का शिलान्यास संत श्री हरि कृपा पीठाधीश्वर स्वामी श्री हरि चैतन्य महाप्रभु के कर कमलों से कश्मीर सिंह पन्नु प्रबंधक, पंकज छावड़ा, प्रधानाध्यापक, अध्यापकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर श्री महाराज ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को मानवोचित संस्कार

विश्वास, कुरीतियों, बुराइयों, भेदभाव, घृणा आदि से। बच्चों को या शिक्षकों को जो भी हम सिखाएँ हमें स्वयं भी अपने

में निरंतर हो रहे मानवता, चरित्र, नैतिकता के हास पर अत्यधिक चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज की शिक्षण संस्थाएं

है। स्वयं को निर्बल और असहाय व असमर्थ ना समझे अपितु निराभमान होकर प्रभु स्मरण करते हुए सही दिशा में

## प्रदेश में परिसीमन से 37 नई ग्राम पंचायतें बढी

देहरादून। चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों का परिसीमन कराया गया था। परिसीमन से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या घटी या बढ़ी है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों के परिसीमन से 37 नई ग्राम पंचायतें वजुद में आ गई हैं। जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या अब 7795 से बढ़कर 7832 हो गई है। पंचायतों के परिसीमन के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों का परिसीमन कराया गया था। परिसीमन से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या घटी या बढ़ी है। विभाग की एक रिपोर्ट में मुताबिक, परिसीमन से 13 पंचायतें घटी हैं। जबकि 50 ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। ऐसे में वास्तविक रूप से 37 ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। टिहरी गढ़वाल में सबसे अधिक 16 पंचायतें, उत्तरकाशी में 13, देहरादून में 8, चमोली में 5, ऊधमसिंह नगर में 4, बागेश्वर में 3 और चंपावत में एक पंचायत बढ़ी हैं। वहीं, ऊधमसिंह नगर व पौड़ी में पांच-पांच, नैनीताल, टिहरी व चमोली में एक-एक ग्राम पंचायत घटी है।



डालकर उन्हें सुसंस्कारित करके समाज का उपयोगी एवं सुयोग्य नागरिक बनाना है। विद्या वह है जो हमें मुक्त कर दे जीवन से नहीं, वरन् अज्ञानता, अंध

जीवन में उसका पालन करना चाहिए। चाहे उसकी आवश्यकता ना हो तो भी अन्याय हमारी शिक्षा का चिरस्थायी प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समाज

भी विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाएं होकर रह गई हैं। उनका भी इस क्षेत्र में योगदान लगभग नगण्य ही होता जा रहा है। जिसके लिए हमें सजग होकर ध्यान देना

## भाजपा का सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाया जाएगा: अग्रवाल

नानकमत्ता (उद संवाददाता)। भाजपा के संस्था अभियान के तहत नगर में एक बैठक का आयोजन किया गया, इसमें भाजपा के सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाने का निर्णय लिया गया। सदस्यता अभियान विधान सभा संयोजक उमेश अग्रवाल ने बताया कि 1 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को सदस्यता दिलवाएंगे। इसके बाद सभी वरिष्ठ नेता, मंत्री सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान को कार्यकर्ता जोर-शोर से



चलाएं। सदस्यता अभियान के लिए ऑनलाइन सदस्यता के अलावा घर-घर जाकर सदस्यता अभियान

चलाने की भी व्यवस्था की गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा से जुड़ने के लिए युवाओं में खासा जोश है।

मुख्य वक्ता अंजू देवी ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सदस्यता अभियान कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा, सदस्यता अभियान संयोजक उमेश अग्रवाल मंडल कार्यक्रम संयोजक जगदीश जोशी, ध्रुव सिंह राणा, निवर्तमान चेयरमैन प्रेम सिंह टुर्ना, वरिष्ठ युवा भाजपा नेता वरुण अग्रवाल, धरम सिंह विष्ट, श्री पाल राणा, ओम नारायण राणा के अलावा वरिष्ठ पदाधि कारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

## गुरु नानक इंटर कॉलेज के छात्र प्रिंस का टेनिस प्रतियोगिता में चयन

नानकमत्ता (उद संवाददाता)। गुरु नानक इंटर कॉलेज नानकमत्ता के छात्र प्रिंस जोशी का चयन राष्ट्रीय स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य तरसेम सिंह ने बताया कि विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 वर्ग में होने वाली सितंबर माह की प्रतियोगिता में कॉलेज के छात्र प्रिंस जोशी का टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चयन किया गया है, जिसको लेकर विद्यालय में खुशी की लहर है, विद्यालय के प्रथम प्रिंस तरसेम सिंह संपूर्ण सिंह तर्जिन्द्र सिंह, डॉ प्रशांत विश्वास ने छात्र को बधाई दी है।



# गुरु माँ एडवांस् डेन्टल क्लीनिक

WORLD-CLASS DENTAL CARE NOW IN YOUR CITY

रूट कैनाल विशेषज्ञ

डेन्टल इम्प्लांट

टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज

डॉ. ऑचल हीगरा

बी.डी.एस., एम.डी.एस., एंडोडोन्टिस्ट  
रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक डेन्टिस्ट  
सर्टिफाइड एस्थेटिक डेन्टिस्ट

Guru Maa Advanced Dental Care "A Multi Speciality Dental Clinic"

१ प्लॉट नं 1, सिविल लाइन्स, रुद्रपुर | ☎ 7452880018, 05944-245666







# नये स्मार्ट औद्योगिक शहरों की श्रृंखला स्थापित करेगा भारत

केंद्र सरकार ने ( एनआईसीडीपी ) के तहत 28,602 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 12 नये परियोजना प्रस्तावों को दी मंजूरी

नई दिल्ली/ देहरादून (उद संवाददाता)। भारत जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य श्रृंखला स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 12 नये परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। जिससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। 10 राज्यों में फैले और रणनीतिक रूप से नियोजित 6 प्रमुख गलियारों के साथ ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाएंगी। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखण्ड में खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिधी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरवाकल और कोणार्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित हैं। एनआईसीडीपी को बड़े एंकर उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) दोनों से निवेश की सुविधा प्रदान करके एक जीवंत औद्योगिक इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये औद्योगिक नोड 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात प्राप्त करने के लिए उल्लेख के रूप में कार्य करेंगे। जो सरकार के आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत के विजन को दर्शाता है। नये औद्योगिक शहरों को वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट

## राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में शामिल हुआ उत्तराखंड का खुरपिया फार्म

देहरादून (उद संवाददाता)। भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत ऊधमसिंह नगर जनपद में स्थित खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित



किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से इस संबंध में विशेष अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री का कहना था कि इस परियोजना के माध्यम से उत्तराखण्ड में 15 हजार करोड़ का निवेश संभावित है और शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। जिन्हें प्लग-एन-प्ले और वॉक-टू-वर्क अवधारणाओं पर मांग से पहले बनाया जाएगा। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस हों। जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक कार्यों का समर्थन करते हैं। पीएम गतिशक्ति



कर करीब 50 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज एनआईसीडीपी के तहत 28,602 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। केंद्र

राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप परियोजनाओं में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा होगा। जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। औद्योगिक शहरों को पूरे क्षेत्र के परिवर्तन के लिए विकास केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इन परियोजनाओं की मंजूरी

शकिसित भारत-एक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भारत को एक मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करके एनआईसीडीपी आवंटन के लिए तत्काल उपलब्ध उन्नत विकसित भूमि प्रदान करेगा। जिससे घरेलू और

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करना आसान हो जाएगा। यह श्रद्धालुनिर्भर भारत या स्ववावलंबी भारत बनाने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है। जो बड़े हुए औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। एनआईसीडीपी से महत्वपूर्ण

में भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से 1002 एकड़ भूमि पर 1265 करोड़ की लागत से स्मार्ट औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री धामी के विशेष प्रयासों से परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करना आसान हो जाएगा। यह श्रद्धालुनिर्भर भारत या स्ववावलंबी भारत बनाने के व्यापक उद्देश्य के अनुरूप है। जो बड़े हुए औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। एनआईसीडीपी से महत्वपूर्ण

रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। जिसमें अनुमानित 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां और नियोजित औद्योगिकरण के माध्यम से 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इससे न केवल आजीविका के अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि उन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में भी योगदान मिलेगा। एनआईसीडीपी के तहत परियोजनाओं को स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है। जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए आईसीटी-सक्षम उपयोगिताओं और हरित प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय और टिकाऊ बुनियादी ढांचा प्रदान करके सरकार का लक्ष्य ऐसे औद्योगिक शहर बनाना है जो न केवल आर्थिक गतिविधि के केंद्र हों, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के मॉडल भी हों। एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स की स्वीकृति भारत की वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एकीकृत विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ ये परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए तैयार हैं। इन नई मंजूरीयों के अलावा एनआईसीडीपी ने पहले ही चार परियोजनाओं को पूरा होते देखा है। चार अन्य वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं। यह निरंतर प्रगति भारत के औद्योगिक क्षेत्र को बदलने और एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

## खुरपिया फार्म के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने की घोषणा को लेकर नगर के व्यापारियों ने जताई खुशी

किच्छा (उद संवाददाता)। खुरपिया को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा को लेकर नगर के व्यापारियों, राजनीतिक, सामाजिक

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण व फैंब्रिकेशन उद्योगों में 6180 करोड़ के निवेश की संभावना है। इससे 75 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वर्तमान

दत्त तिवारी के बाद पहली बार प्रदेश को इंडस्ट्रीज पार्क मिला है इसके लिए केंद्र की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर

आसानी होगी। खुरपिया में नया औद्योगिक क्षेत्र बनने से पंतनगर, रुद्रपुर व काशीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में लगे उद्योगों को भी फायदा होगा। स्थानीय लोगों और

## सांसद अजय भट्ट ने किच्छा को इंडस्ट्रीयल स्मार्ट सिटी की सौगात देने पर जताया आभार

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। पूर्व केंद्रीय मंत्री व नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता की केंद्रीय कैबिनेट में हुई बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के 12 शहरों में 28602 करोड़ की लागत से औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है जिसमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खुरपिया फार्म को इंडस्ट्रीयल स्मार्ट सिटी की सौगात मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताया है, सांसद भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के खुरपिया में इंडस्ट्रीयल स्मार्ट सिटी की सौगात से प्रदेश में विनिर्माण क्षमता और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे उन्होंने पुनः प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है।



संजीव खन्ना का मानना है कि इससे क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे तथा रोजगार के संसाधन भी विकसित होंगे। राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक स्मार्ट सिटी विनिर्माण क्षमता व आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे प्रदेश में निवेश में वृद्धि होगी, वहीं बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। किच्छा में औद्योगिक स्मार्ट सिटी का बड़ा निर्णय है। स्मार्ट सिटी को लेकर खुरपिया फार्म में स्थित जमीन सिडकुल को हस्तांतरित हो चुकी है।



संगठनों ने खुशी का इजहार करते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की पहल का स्वागत किया है। 1002 एकड़ में बनने वाले औद्योगिक में ऑटोमोबाइल,

विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा है कि किच्छा के खुरपिया क्षेत्र में सरकार द्वारा निवेश को लेकर रोजगार के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण

सिंह धामी आभार व्यक्त करते हैं। निवर्तमान पालिकाध्यक्ष दर्शन कोली ने कहा कि यह क्षेत्र एयर, रेल व रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा होने से निवेशकों को

जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, जिनमें विजयपाल यादव, गुलशन सिंधी, विजय अरोड़ा, राजकुमार बजाज, नितिन फुटेला, डॉ एके गुप्ता, सतपाल गावा,

### गुरुजी

# उत्तराखंड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन

गर्मियों में ठंड जैसी राहत

गुरुजी

36 महीने तक की EMI उपलब्ध

**Budget Ac**

**Premium Split Ac**

**Mid-Range Split Ac**

**Heavy-Duty Split Ac**

**SONY** **Whirlpool** **SAMSUNG** **IFB** **Haier** **BOSCH** **VOLTAS**

**DAIKIN** **HITACHI** **MITSUBISHI** **GENERAL** **LLOYD** **BLUE STAR**

**Refrigerator की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध**

**Deep Freezer की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध**

**RO Purifier की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध**

**Water Dispencer की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध**

**Air Cooler की सबसे बड़ी रेंज उपलब्ध**

**Easy EMI Options Available**

RUDRAPUR- Civil Line +91-9927882338, Kashipur Bypass +91-9690282777, Kashipur Bypass +91-9756233166, Sony Center +91-9917170230 KASHIPUR- Ramnagar Road +91 8791989500, Cheema Chauraha +91 9927813555 HALDWANI- Tikonia +91-9997207007, Piliikothi +91-8923468434, Piliikothi +91-9690256666, HARIDWAR- Haridwar +91-9761699704 MORADABAD- Moradabad +91-7500839146, GADARPUR- Near Super Market +91-9927850999, KICHHA- Kichha +91-7017595920, LOHAGHAT- Daak Bangla Road +91-9568035735 DEHRADUN- Kaluagarh Road +91-8394949454 PANIPAT- West Market Opp. Central Bank +91-8607964000 KARNAL- Mangal Singh Market +91-8684077000, 49 Ram Nagar +91-8908350000